7 .8% जीडीपी वृद्धि पर छिड़ी बड़ी बहस

सरकार ने आर्थिक वृद्धि के आंकड़े का किया बचाव, पुरानी और नई जीडीपी श्रृंखला की तुलना पर उठाए सवाल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली ,03 सितंबर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर को लेकर आर्थिक जगत में बहस तेज हो गई है. सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें नई जीडीपी श्रृंखला के आधार पर जारी वृद्धि दर पर सवाल उठाते हुए इसे करीब 2.6 प्रतिशत बताया गया है.

सौरभ गर्ग के मुताबिक, स्टील, सीमेंट और वाहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है . ऐसे में सरकार का कहना है कि पहली तिमाही में दर्ज 7 .8 प्रतिशत की वृद्धि अर्थव्यवस्था में जारी ठोस उत्पादन गतिविधियों को दर्शाती है . सरकार ने पुरानी और नई जीडीपी श्रृंखला के आंकड़ों को आपस में मिलाकर वृद्धि दर पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है .

सरकार का कहना है कि मौजूदा जीडीपी अनुमान की तुलना पुरानी और अब बदली जा चुकी श्रृंखला के आंकड़ों से करना सही नहीं है. यह तुलना 'सेब और संतरे' की तरह है, क्योंकि दोनों के आधार और गणना पद्धति अलग हैं.सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की टिप्पणी के बाद सरकार का पक्ष स्पष्ट किया. पूर्व वित्त सचिव का तर्क था कि यदि पिछले साल की जून तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े को करीब 86 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपए नहीं किया जाता, तो मौजूदा कीमतों पर पहली तिमाही की वृद्धि दर करीब 2.6 प्रतिशत ही रहती.सांख्यिकी सचिव ने इस तर्क को सही नहीं माना. उन्होंने कहा कि इसमें स्थिर कीमतों के बजाय मौजूदा कीमतों के आंकड़ों की तुलना की गई है.

इसके अलावा 86.05 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा 2011-12 आधार वर्ष वाली पुरानी जीडीपी श्रृंखला से जुड़ा था, जबकि वर्तमान अनुमान 2022-23 आधार वर्ष वाली नई श्रृंखला के तहत तैयार किया गया है.

महानदी कोलफील्डस का आईपीओ

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 03 सितंबर महानदी कोलफील्डस लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं. प्रस्तावित आईपीओ के तहत उसकी प्रवर्तक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी दस्तावेजों के मौदा के अनुसार आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश के रूप में होगा. इसके तहत कोल इंडिया एमसीएल के 66,18,36,300 शेयर बेचेगी. इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा डीआरएचपी 31 अगस्त को दखल किया गया निर्णम में केवल ओएफएस शामिल होने के कारण ओडिशा स्थित एमसीएल को आईपीओ से कोई राशि नहीं मिलेगी.

स्क्रैपिंग बढ़ाएं, वाहन बिक्री बढ़ेगी : गडकरी

- **देश में हर साल एक लाख से ज्यादा बसों की मांग**
- **इलेक्ट्रिक बसों के साथ ड्राइवर प्रशिक्षण बढ़ाने पर जोर**

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली,03 सितंबर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों से पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों की बिक्री बढ़ने के साथ उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होगा और लागत भी कम होगी.

मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बसों की मांग और मौजूदा उत्पादन क्षमता के बीच अंतर का भी मुद्दा उठाया . उनके मुताबिक देश में हर साल एक लाख से अधिक बसों की जरूरत है, जबकि वर्तमान विनिर्माण क्षमता करीब 70 हजार बसों की है . उन्होंने कंपनियों से विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया . इसके अलावा गडकरी ने वाहन कंपनियों से ड्राइवर प्रशिक्षण में भी योगदान देने की अपील की . उन्होंने कहा कि कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड का इस्तेमाल ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए कर सकती हैं . इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी .

भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के 66वें वार्षिक सम्मेलन में गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग का फायदा सीधे वाहन उद्योग को मिलेगा. उन्होंने कंपनियों से इस दिशा में और निवेश करने की अपील की.

गडकरी ने देश में किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि मेट्रो के निर्माण की लागत करीब 350 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंचती है. बड़े शहरों में यह मॉडल व्यावहारिक हो सकता है, लेकिन छोटे शहरों के लिए कम लागत वाले परिवहन विकल्प तलाशने होंगे. पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे को उन्होंने एक उपयोगी विकल्प बताया.

एआई+ स्मार्टफोन ने प्राइवेसी मजबूत करने के लिए नया ओएस किया पेश

नवभारत, जबलपुर। एआई+ स्मार्टफोन ने एनएक्सटी क्वांटम ओएस का नया वर्जन 1.1 पेश किया है जो भारत में कोर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्स कोड को सुरक्षित रखते हुए यूज़र्स की प्राइवेसी व कंट्रोल को मजबूत करेगा। प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के लिए एनएक्सटी क्वांटम ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसके तहत ऐप्स का शत-प्रतिशत डेटा ट्रैफिक और आईपी पिंग्स भारत में मौजूद सर्वर्स के जरिए ही प्रोसेस होंगे, जबकि कुछ सामान्य ओएस सर्विसेस के लिए जरूरी गूगल कोर सर्विसेस का डेटा ट्रैफिक कैलिफोर्निया और सिंगापुर जाएगा। यूज़र्स की सुविधा के लिए इसमें एनएक्सटी प्राइवेसी डैशबोर्ड और प्राइवेसी अलर्ट भी शामिल किया गया है जिससे ऐप्स की परमिशन्स को एक ही जगह देखने और उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक बदलने या बंद

करने की आसान सुविधा मिलेगी। इस नए अपडेट पर बात करते हुए एनएक्सटीक्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीस और एआई+ स्मार्टफोन के सीईओ माधव शेठ ने कहा कि टेक्नोलॉजी का भविष्य इस बात से तय होता है कि लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं और यही भरोसा हमारी सोच का अहम हिस्सा है। यूज़र्स को अधिक पारदर्शिता देने का यह प्रयास प्रोजेक्ट ओपन रिव्यू 2.0 में भी दिखाई देता है जिसके तहत रिव्यूअर्स, क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट्स और एथिकल हैकर्स लॉन्च से पहले इन डिवाइसेस को खुद टेस्ट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं।

आरबीआई बोर्ड में सैयद अकबरुद्दीन नियुक्त

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली,03 सितंबर पूर्व राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में चार वर्ष के लिए अंशकालिक, गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है.

नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. अकबरुद्दीन के साथ वित्त मंत्रालय की पूर्व विशेष सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया के चेयरमैन जनमेजय कुमार सिन्हा को भी बोर्ड में शामिल किया गया है. 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अकबरुद्दीन को अंतरराष्ट्रीय मामलों, कूटनीति और शासन का तीन दशक से अधिक का अनुभव है.

वीआईटी चेन्नई में तकनीकी महोत्सव शुरू

नवभारत कनेक्ट

चेन्नई, 3 सितंबर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) चेन्नई के विद्यार्थियों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव 'टेक्नोवीआईटी'26' का गुरुवार, 3 सितंबर को शुभारंभ हुआ।

दो दिवसीय यह महोत्सव 3 और 4 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में चेन्नई स्थित रूसी संघ के महावाणिज्य दूतावास के उप महावाणिज्यदूत अलेक्जेंडर फोमिन मुख्य अतिथि रहे, जबकि डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के उपाध्यक्ष-संचालन एवं लॉजिस्टिक्स अरुलसेल्वम हरिकृष्णन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संस्थापक एवं कुलाधिपति डॉ. जी. विश्वनाथन ने समारोह की अध्यक्षता की। वीआईटी के उपाध्यक्ष डॉ. जी.वी. सेल्वम ने विशेष संबोधन दिया। इस वर्ष 'टेक्नोवीआईटी'26' की थीम 'समावेशी नवाचार' रखी गई है। महोत्सव में 140 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें भारत के अलावा 14 देशों से प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, जापान, फ्रांस, नॉर्वे, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और उत्तरी अमेरिका से प्रतिभागी महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 15 हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।

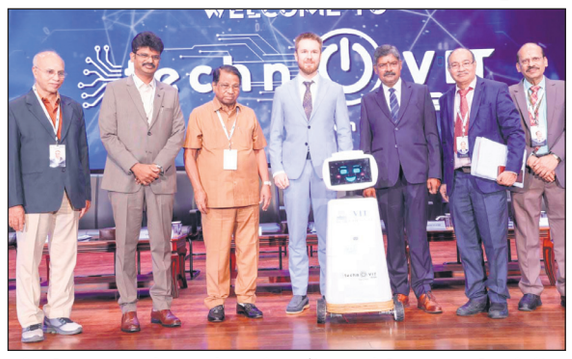

गोयल जाएंगे अमेरिका, व्यापार वार्ता को मिलेगी रफ्तार

- **जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा**
- **द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत में प्रगति का दावा**

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली 03, सितंबर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे. इस दौरान वह वॉशिंगटन में होने वाली जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के साथ भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत पर भी चर्चा करेंगे.

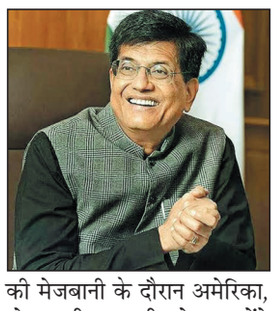

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार मिलकर काम कर रहे हैं और बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है.ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के 66वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन में जी20 से जुड़ी बैठकों की मेजबानी के दौरान अमेरिका, गोयल की अगवानी करेगा. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ऐसे व्यापारिक संबंध विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो निष्पक्ष, पारस्परिक और दोनों देशों के लिए लाभकारी हों.

गोयल की प्रस्तावित यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं. अमेरिकी राजदूत ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत बताते हुए कहा कि दोनों सरकारें कई स्तरों पर करीब से काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच काफी गतिविधियां चल रही हैं और वॉशिंगटन जी20 बैठकों के लिए गोयल की मेजबानी को लेकर उत्सुक है.

गोयल ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधी समझ और अब तक हुई प्रगति का भी उल्लेख किया . उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका सहयोग केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश कई दूसरे क्षेत्रों में भी साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं .अमेरिकी राजदूत ने व्यापक आर्थिक सहयोग का जिक्र करते हुए इस साल की शुरुआत में हस्ताक्षरित पैक्ट सिलिका घोषणा का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, इसका उद्देश्य ऐसा नियामकीय ढांचा तैयार करना है, जो नवाचार को बढ़ावा दे और अमेरिकी तथा भारतीय कंपनियों के बीच सीमा-पार निवेश को प्रोत्साहित करे .

एसयूएम नर्सिंग कॉलेज में पोषण जागरुकता

नवभारत कनेक्ट

भुवनेश्वर, 3 सितंबर. भुवनेश्वर के बाहरी क्षेत्र स्थित दारुथेंगा गांव में गुरुवार को एसयूएम नर्सिंग कॉलेज (एसएनसी) की ओर से पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में उचित पोषण, स्वस्थ खान-पान की आदतों, शारीरिक विकास और कुपोषण की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

एसओए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के नर्सिंग संकाय एसएनसी के सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, बच्चों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने भाग लिया। एसएनसी के प्रथम वर्ष के एमएससी नर्सिंग विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में पांच वर्ष से

कम उम्र के बच्चों के पोषण संबंधी आकलन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डाला।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया

नवभारत कनेक्ट

उदयपुर , 03 कंपनी ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ बीएसई 500 मोमेंटम वैल्यू 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है. यह 'वैल्यू और मोमेंटम' (मूल्य और रुझान) पर आधारित निवेश विकल्प है, जो ग्राहकों को चुनिंदा यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) के ज़रिए दीर्घकालिक स्तर पर इक्विटी में निवेश के अवसर का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है.

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य निवेश अधिकारी, श्री मनीष कुमार ने लॉन्च पर अपनी टिप्पणी में कहा, 'बीएसई 500 मोमेंटम वैल्यू 50 इंडेक्स फंड को ग्राहकों को एक अनुशासित और पारदर्शी निवेश रणनीति प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जो निवेश के दो महत्वपूर्ण कारकों-वैल्यू और मोमेंटम को जोड़ता है. ऐसे में, जहाँ आकर्षक मूल्यांकन से बेहतर मूल्य पर खरीद का भरोसा मिल सकता है, वहीं सकारात्मक रुझान से बाज़ार का बढ़ता भरोसा ज़ाहिर हो सकता है. यह रणनीति इन दो तत्वों को मिलाकर उन कंपनियों की पहचान कर पाती है, जो दोनों पैमानों पर मज़बूत दिखती हैं. इससे निवेशकों को मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए उभरते अवसरों में भाग लेने में मदद मिलती है.'

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE
Ke Saath Zimmedari Lagey Pyaari
Trusted by over 20 crore Indians in 25 YEARS

उन्होंने कहा, 'इस रणनीति के तहत व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन किया जाता है और तिमाही स्तर पर पोर्टफोलियो की समीक्षा की जाती है, जिससे यह बदलते बाज़ार मूल्यांकन और रुझान के साथ विकसित हो पाता है. हमारा मानना ??है कि इस दृष्टिकोण से ग्राहकों को निवेश अनुशासन बनाए रखते हुए दीर्घकालिक इक्विटी वृद्धि में भाग लेने का अलग तरीका मिल सकता है.'

समाचार विशेष

त्रिकोणीय हो सकती है आदिवासी राजनीति

जमशेदपुर, 3 सितंबर. झारखंड में परिसीमन के मुद्दे पर आदिवासी समुदाय का हालिया बड़ा जुटान सिर्फ परिसीमन की आशंकाओं तक सीमित राजनीतिक घटनाक्रम नहीं माना जा रहा है. रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की की अगुवाई में जुटी भारी भीड़ ने राज्य के सियासी गलियारों में एक नया और दूरगामी संदेश दिया है.

इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस अब झारखंड में आदिवासी राजनीति के उस बड़े हिस्से पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की तैयारी कर रही है, जिसे लंबे समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन मानता रहा है? झारखंड में सत्ता की राजनीति का सबसे बड़ा आधार आदिवासी मतदाता हैं.

राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं. ऐसे में आदिवासी हितों और अस्तित्व से जुड़े किसी भी बड़े मुद्दे पर राजनीतिक नेतृत्व और जनसमर्थन का ऐसा प्रदर्शन आने वाले चुनावी समीकरणों की दिशा तय करता है. परिसीमन को लेकर आदिवासी समुदाय के भीतर यह गहरी आशंका है कि जनसंख्या के बदलते स्वरूप और डेमोग्राफिक बदलावों का सीधा असर भविष्य में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है. यही आशंका अब राज्य के मुख्य राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन रही है.

झामुमो के एकाधिकार को चुनौती

कांग्रेस लंबे समय से राज्य में झामुमो की मुख्य सहयोगी रही है और मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में भी दोनों दल बराबर के साझेदार हैं . लेकिन गठबंधन की राजनीति का व्यावहारिक सच यह है कि इसमें सहयोग और चुनावी प्रतिस्पर्धा साथ-साथ चलते हैं . झामुमो की पूरी राजनीति का केंद्रीय आधार आदिवासी अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और अलग झारखंड आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत रही है . हेमंत सोरेन ने इस आधार को और अधिक धार दी है . ऐसे में यदि कांग्रेस आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपना कैडर, संगठन और नेतृत्व आक्रामक तरीके से बढ़ाती है, तो 2029 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछते ही सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के नेतृत्व तक कई तीखे सवाल उठना स्वाभाविक है .

भाजपा-शिअद के संगठनों का पीयू में गठबंधन

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर लगने लगे सियासी कयास

चंडीगढ़, 3 सितंबर. पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन क्या हुआ कि पंजाब विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी कयास लगने शुरू हो गए.

गठबंधन भले ही भाजपा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और शिअद के छात्र संगठन सोई के बीच हुआ हो, लेकिन इसे पंजाब विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है. क्योंकि छात्र संघ चुनाव का पंजाब की राजनीति पर हमेशा ही बड़ा असर देखने को मिलता रहा है.

2020 में कृषि कानून को

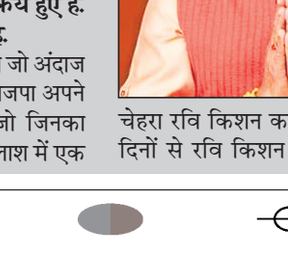

लेकर दोनों पार्टियों के बीच टूटे गठबंधन के बाद यह पहला मौका है जब दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं. यह चुनाव भले ही छात्रों का हो लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है. पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने तो अपने सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को चुनाव की जिम्मेदारी सौंप रखी है. जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी छात्र संघ चुनाव में पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं. मतदान से एक दिन पहले एबीवीपी और सोई के बीच हुए गठबंधन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के गुणा भाग को बिगाड़ दिया. क्योंकि इसका असर पंजाब में विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है. पंजाब चुनाव को लेकर भाजपा और शिअद के बीच गठबंधन की चर्चा तेजी से चल रही है. क्योंकि माना यह जा रहा है कि अगर पंजाब में दोनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो विपक्षी पार्टियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

आगे भी दोनों पार्टियां आ सकती हैं साथ

वहीं, छात्र संघ चुनाव के जरिए ही सही दोनों पार्टियों के करीब आने से यह संकेत मिलने लगे हैं कि आगे भी दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं. क्योंकि 2015 में पंजाब बेअदबी कांड के बाद से पीयू में दोनों ही पार्टियां अलग-अलग ही चुनाव लड़ती रही हैं . 2020 में अधिकारिक रूप से दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया था. 24 अगस्त को हुए छात्रसंघ चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान सोई से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रणव की पात्रता को लेकर विवाद हुआ था.

नीतीश की चाणक्य चाल में ध्वस्त मिशन लव कुश!

पटना, 3 सितंबर. लव-कुश जयंती सह सम्मान समारोह के समय से पहले ही स्थगित हो जाने के बाद बिहार की राजनीति में कई सवाल उठ गए हैं. बापू सभागार में 30 अगस्त को लव-कुश जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. ये आयोजन लव-कुश प्रोग्रेसिव ग्रुप बिहार के द्वारा होना था. इस आयोजन के बड़े बड़े लक्ष्य थे.

इस आयोजन के सापेक्ष पोस्टरों में एक बड़े जुटान की तस्वीर भी दिख रही थी. ऐसा लगा कि वर्ष 1994 में आयोजित कुर्मी चेतना रैली एक बार फिर दोहराई जाएगा. तब नीतीश कुमार और सतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था और 30 अगस्त 2026 को राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में होगा. लेकिन अचानक सड़क से लव-कुश सह सम्मान समारोह का फेसबुकिया सूचना से अंत हो जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के हार के कारणों में लव के नाराज होने की अंदरूनी खबर से सम्राट सराकार बैचेन हो उठी. बेचैन होने की बात भी थी. ऐसा इसलिए कि इसी लव कुश के सहारे नीतीश कुमार ने ढाई दशक तक सत्ता की बागडोर अपने हाथ रखी. इन खास लोगो में नाराजगी इस बात की है कि आखिर नीतीश कुमार को जब मैंडेट मिला तो उन्हें हटाया क्यों गया? इस लव कुश को एक पटरी पर लाने के ख्याल से लव कुश जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया या कराया गया.

नीतीश ने ही ना कह दिया!

राजनीतिक गलियारों में चल रही गपशप की मानें तो इस लव-कुश जयंती सह सम्मान समारोह के प्रति नीतीश कुमार ने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई . चर्चा यह है कि कुर्मी निशांत कुमार को नेता मानने को तैयार हैं . वे उनके नेतृत्व में ही बिहार का और अपना भविष्य देखना चाहते हैं . एक चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार जातीय सम्मेलन से परहेज करते हैं . वर्ष 1994 में आयोजित कुर्मी चेतना रैली में भी वे नहीं जाना चाहते थे . वे तब अपने समाज के दबाव में चले गए . और इस बार 30 अगस्त को बापू सभागार में आयोजित लव-कुश जयंती सह सम्मान समारोह में भी कहा जा रहा है कि नीतीश ने समाज के कारण ही लव कुश जयंती समारोह में जाने से मना कर दिया .

विशेष | **पिछले कुछ दिनों से रवि किशन की पीआर टीम बहुत सक्रिय है**

रवि किशन से भाजपा की उम्मीदें

नई दिल्ली, 3 सितंबर. भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से युवाओं और खास कर 'जेन जी' की नाराजगी दूर करने और उसके साथ कनेक्ट बढ़ाने के लिए बेचैन है. जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल रहे थे और उसके बाद उनकी सरकार के मंत्री और पार्टी के नेता इंस्टाग्राम पर सक्रिय हुए हैं. उससे इसका अंदाजा लग रहा है.

रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री का जो अंदाज था वह भी नयापन लिए हुए थे. भाजपा अपने ऐसे नेताओं को खोज रही है, जो जिनका कनेक्ट युवाओं से हो सके. इस तलाश में एक

चेहरा रवि किशन का उभरा है. पिछले कुछ दिनों से रवि किशन की पीआर टीम बहुत सक्रिय है. उनके पुराने भाषणों की मीम्स, रील्स आदि खूब सरकुलेट किए जा रहे हैं. पिछले दिनों वे युवाओं के एक कार्यक्रम में गए तो उन्होंने मंच पर स्टाइलिश डांस किया, जिसे सोशल मीडिया में बहुत पसंद किया गया. उसके बाद से रवि किशन के प्रमोशन की चर्चा तेज हो गई है. रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ हिंदी और दक्षिण भारत की अनेक भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं. वे गोरखपुर से सांसद हैं. अब कहा जा रहा है कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है. भाजपा उनकी लोकप्रियता का अधिकतम लाभ लेना चाहती है.